

तमिलनाडु जनरेशन और वितरण निगम लिमिटेड (TANGEDCO) जरीये अध्यक्ष व  
प्रबंधक और अन्य

बनाम

CSEPMI - TRISHE कंसोर्टियम, जबाबी जरीये प्रबंधन निदेशक और अन्य

(सिविल अपील सं. 10182-10183/2016)

18 अक्टूबर, 2016

[दीपक मिश्रा और शिवकीर्ति सिंह, जे. जे.]

निविदा-बोली को अंतिम रूप देना-सलाहकार द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट-न्यायिक समीक्षा-आयोजित: एक जटिल वित्तीय मूल्यांकन में, अदालत को संयम के सिद्धांत को लागू करना पड़ता है-वित्तीय गणना शामिल है, बोली लगाने वाले की क्षमता और दक्षता और परियोजना को पूरा करने की व्यवहार्यता की धारणा को वित्तीय विशेषज्ञों और सलाहकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिनके पास इस क्षेत्र में ज्ञान और कौशल है-अदालतें वास्तव में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं-यदि अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग इस तरह से करेंगी कि इससे भ्रम पैदा होने की संभावना है और सार्वजनिक हित में भी खतरा पैदा हो सकता है-इसके अलावा, एक पीड़ित पक्ष उचित स्तर पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, न कि जब बोलियों पर विचार किया जा रहा हो। तथ्यों पर, सलाहकार ने निविदा की शर्तों के संबंध में प्रस्तावों का विश्लेषण और निर्धारण किया-मालिक द्वारा दोनों योग्य बोलीदाताओं से पारदर्शी तरीके से दस्तावेज मांगे गए थे और सलाहकार द्वारा मूल्यांकन के समय उन पर विचार किया गया था-यह दोनों पक्षों से कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त करने से पहले किया गया था-इस प्रकार, खंड पीठ ने एक अपीलिय मंच या प्राधिकरण के दृष्टिकोण को अपनाने में गलती की और न्यायिक

समीक्षा के सिद्धांत को कुछ क्षेत्रों तक बढ़ाया-खंड पीठ के आदेश को दरकिनार कर दिया-तमिलनाडु निविदा अधिनियम में पारदर्शिता, 1998।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 यह स्पष्ट है कि निगम ने 30-01-2014 पर आयोजित अपनी बैठक में दोनों बोलीदाताओं पर मूल्य बोलियां खोलने का निर्णय लिया था और उसके बाद दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत तकनीकी विचलन के संबंध में अतिरिक्त प्रभाव वाली वस्तुओं के लिए दोनों पक्षों से पूरक मूल्य बोलियां प्राप्त की गईं और उसके बाद 05-02-2014 पर मूल्य बोलियां खोली गईं। जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है, मूल्य बोलियों का मूल्यांकन सलाहकार द्वारा किया गया था। एकल न्यायाधीश ने सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मूल्य मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। (पैरा 15) (503-डी-एफ)

1.2 सलाहकार द्वारा मूल्य मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 का ई. पी. सी. मूल्य Rs.9207.264 करोड़ था और प्रत्यर्थी संख्या 2 जिसे अनुबंध दिया गया था वह Rs.7762.977 करोड़ था। इस प्रकार, दो ई. पी. सी. मूल्यों के बीच का अंतर Rs.1444.287 करोड़ है। प्रथम प्रत्यर्थी ने सलाहकार द्वारा मूल्य मूल्यांकन रिपोर्ट पर इस आधार पर विवाद किया कि उसने प्रतिबद्धता शुल्क, मेरी अवधि के दौरान प्रबंधन शुल्क पर ब्याज और जे. डी. सी. अवधि के दौरान अपनी बोली राशि में गारंटी शुल्क के ब्याज के लिए राशि को गलत तरीके से लोड किया, जिसके कारण ब्याज के साथ उद्धृत वित्तीय शुल्कों का मूल्यांकन Rs.801.18 करोड़ किया गया था। (पैरा 16) (505-सी-एफ)

1.3 सलाहकार की रिपोर्ट की शुद्धता से संबंधित मुद्दे को तथ्यात्मक अंक प्राप्त करने में न्यायिक समीक्षा की सीमित शक्ति के दायरे में निर्णय और जांच की जानी चाहिए। खंड पीठ ने विवादित फैसले में एल. 1 की पहचान में अपनाई गई प्रक्रिया पर

आपत्ति जताई है। इसने अपने दिनांकित 19.8.2014 आदेश का उल्लेख किया है जिसमें प्रथम प्रतिवादी को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया था। विवादित आदेश में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि उस समय निगम ने कभी यह नहीं माना था कि निविदा को अंतिम रूप दिया गया था। इसने डिवीजन बेंच के पहले के आदेश का उल्लेख किया है कि अभ्यावेदन पर विचार किया जाना चाहिए और तब तक बोली को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। इसने निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के दिनांकित 20.7.2014 के पत्र का उल्लेख किया है और राय दी है कि यह तथ्य का गलत विवरण प्रतीत होता है। (पैरा 21) (509-बी-डी)

1.4 प्रबंधन और गारंटी शुल्क पर ब्याज पर निगम का रुख यह है कि प्रतिवादी नं. 1 प्रबंधन शुल्क के रूप में 123.9746 करोड़ रु. और उनकी मूल्य बोली में गारंटी शुल्क के रूप में 392.0163 करोड़ रु. शुल्क की मात्रा को लेकर कोई विवाद नहीं है। मूल्यांकन के दौरान सलाहकार ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड की टर्म शीट के अनुसार उपरोक्त शुल्कों पर 7.7 प्रति वर्ष की दर से ब्याज निर्धारित किया है, क्योंकि उपरोक्त शुल्क अपीलकर्ता द्वारा चुकाए जाने वाले ऋण का हिस्सा हैं; यह निविदा शर्तों के साथ-साथ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए टर्म शीट और 21.10.2013 (इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड द्वारा जारी) के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता पूरे ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें वित्तीय शुल्क शामिल होंगे। [पैरा 34) [520-सी-ई]

1.5 यह स्पष्ट है कि सलाहकार ने निविदा शर्तों के संबंध में प्रस्तावों का विश्लेषण किया। चाहे यह माना जाए कि वित्तीय सलाहकार द्वारा किया गया विश्लेषण और निर्धारण दोनों पक्षों से किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज की प्राप्ति से पहले किया गया था। मालिक द्वारा दोनों योग्य बोलीदाताओं से पारदर्शी तरीके से दस्तावेज मांगे गए थे और

सलाहकार द्वारा मूल्यांकन के समय उन पर विचार किया गया था। प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि मूल्यांकन स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है क्योंकि सलाहकार ने कुछ शुल्क लगाए हैं जिसके परिणामस्वरूप कीमत बढ़ गई है। बी. एच. ई. एल. के वकील और निगम की ओर से पेश वकील ने कहा कि मूल्यांकन परिभाषाओं पर आधारित है और किसी भी प्रकार की आकस्मिकता के लिए कुछ नहीं छोड़ता है। उन्होंने टर्म शीट और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड द्वारा क्या रखा गया था, इसका उल्लेख किया। एक जटिल राजकोषीय मूल्यांकन में न्यायालय को संयम के सिद्धांत को लागू करना पड़ता है। कई पहलुओं, खंडों, आकस्मिकताओं आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन गणनाओं को विशेषज्ञों और उन लोगों पर छोड़ दिया जाता है जिनके पास इस क्षेत्र में ज्ञान और कौशल है। वित्तीय गणना, बोली लगाने वाले की क्षमता और दक्षता और परियोजना को पूरा करने की व्यवहार्यता की धारणा को वित्तीय विशेषज्ञों और सलाहकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। न्यायालय वास्तव में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह न तो प्रत्यक्ष रूप से गलत है और न ही इसे विकृत या बेतुका होने के लिए त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है। (पैरा 36) (521-एफ-एच; 522-ए-सी)}

1.6 प्रत्यर्थी ने वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने से पहले कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए और मालिक की खामोशी को देखते हुए रिट अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी, जिसने अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय को उस स्तर पर सावधानी बरतनी चाहिए थी। यदि अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग इस तरह से करती हैं तो इससे भ्रम पैदा होने और सार्वजनिक हित को भी खतरे में डालने की संभावना है। एक पीड़ित पक्ष उचित स्तर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, न कि जब बोलियों पर विचार किया जा रहा हो। यह सराहनीय है कि कुछ प्रकार की निविदाओं में मालिक निष्पक्षता दिखाने के लिए बोलीदाताओं को बातचीत के लिए

बुलाता है। लेकिन तत्काल मामला ऐसी प्रकृति का नहीं है। एक बार मूल्य बोली खोले जाने के बाद, एक बोलीदाता अपने दम पर अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता था और कुछ पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए न्यायालय से एक आदेश की मांग नहीं कर सकता था। यह पहलू केवल संयम के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की भूमिका को उजागर करने के लिए है। [पैरा 37] [522-डी-एफ]

1.7 खंड पीठ ने परिसीमन के माध्यम से एक अपीलीय मंच या प्राधिकरण के दृष्टिकोण को अपनाया है और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को कुछ क्षेत्रों तक विस्तारित किया है जिन पर वह नहीं हो सकता था और इसलिए, खंड पीठ के निर्णय और आदेश ने निरंतरता में त्रुटि के मार्ग का अनुसरण किया। [पैरा 38] [522-जी]

जगदीश मांडा बनाम उड़ीसा राज्य 2006 (10) पूरक एस. सी. आर. 606: (2007) 14 एस. सी. सी. 517; स्टार एंटरप्राइजेज बनाम सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड 1990 (2) एस. सी. आर. 826: (1990) 3 एस. सी. सी. 280-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ 2006 (10) पूरक पैरा 11 1990 (2) एस. सी. आर. 826 को संदर्भित एस. सी. आर. 606 पैरा 11 को संदर्भित।

सिविल अपीलेट क्षेत्राधिकारिता: सिविल अपील सं. 10182-10183/2016

2015 के डब्ल्यू. ए. सं. 712 और 713 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 07-09-2015 से उत्पन्न।

साथ में

2016 की सिविल अपील सं. 10184-10185

मुकुल रोहतगी, ए. जी., पराग पी. त्रिपाठी, एल. नागेश्वर राव, सुब्रमण्यम प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, अतुल शंकर माथुर, सुश्री निमीता कौल, सुश्री श्वेता सिंह (मैसर्स खेतान

एंड कंपनी के लिए), मयंक पांडे, सुश्री मेहा अग्रवाल, बी. बालाजी, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता।

कपिल सिब्बल, श्रीराम पंचू, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौतम नारायण, एन. एल. राजा, अरुण अंबुमणि, संतनम स्वामीनाथन, गौतम नारायण, एन. एल. राजा, अरुण अंबुमणि, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई

2. अपीलार्थी, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में 'निगम') ने दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से एन. सी. टी. पी. एस., चेन्नई के एश डाइक में 660 मेगावाट की एन्नोर एस. ई. जेड. सुपरक्रिसिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दो इकाइयों की स्थापना के लिए एक निविदा जारी की, जिसमें उत्तरदाताओं सहित चार बोलीदाताओं ने भाग लिया। हालांकि, चार में से दो बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि वे बोली योग्यता आवश्यकताओं (बीक्यूआर) को पूरा करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप कंसोर्टियम ऑफ ट्रिंश एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सीएसईपीडीजे) और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) की बोलियों पर विचार किया गया। मूल्य बोली शुरू होने से पहले, सी. एस. ई. पी. डी. जे. और बी. एच. ई. एल. ने 05.02.2014 पर पूरक मूल्य बोलियां प्रस्तुत कीं। योग्य बोलीदाताओं, उत्तरदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अपीलार्थी द्वारा 05.02.2014 पर मूल्य बोलियां खोली गईं।

3. तथ्यों के अप्रमाणित होने से यह पता चलता है कि "प्रत्यर्थी ने बोली के विभिन्न पहलुओं और" बोलीदाताओं को निर्देश "(आई. टी. बी.) के खंड 29 के पैरा (viii) की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए अपीलार्थी को 16.06.2014, 17.06.2014,

01.07.2014 और 08.07.2014 दिनांकित अभ्यावेदनों की श्रृंखला भेजी, जो बोलीदाता की बोलियों की अस्वीकृति से भी संबंधित है, जिसका पिछला प्रदर्शन/विक्रेता मूल्यांकन संतोषजनक नहीं है। चूंकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. द्वारा किए गए अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसने 2014 का डब्ल्यू. पी. सं. 19247 दायर किया, जिसमें अपीलार्थी को अभ्यावेदन पर विचार करने और तमिलनाडु निविदाओं में पारदर्शिता अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, "टी. टी. आई. टी. अधिनियम") का पालन करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य रिट जारी करने की मांग की गई। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक वचन दिया गया था कि बोली के बाद प्रत्यर्थी नं। निविदाओं को अंतिम रूप देते समय मुझ पर विधिवत विचार किया जाएगा और निविदा विनिर्देशों और टी. टी. आई. टी. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित आदेश पारित किए जाएंगे और उक्त उपक्रम के संदर्भ में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 31.07.2014 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को प्रतिवादी नं. मैंने उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्देश दिया कि जब तक इस तरह के आदेश पारित नहीं हो जाते, तब तक निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

4. उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने डिवीजन बेंच के समक्ष 2014 की डब्ल्यू. ए. संख्या 1065 की रिट अपील दायर की, जिसने निर्णय और दिनांक 19.08.2014 के आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को केवल इस हद तक संशोधित करके रिट अपील का निपटारा किया कि व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करना इस हद तक अस्वीकार्य था कि नियमों (संक्षेप में, "नियमों") के तहत विचार नहीं किया गया था और आगे प्रतिवादी संख्या 1 को अनुमति दी। मैं अपनी सभी आपत्तियों को उठाते हुए अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करता हूं और अपीलार्थी को एक आदेश पारित करने और उत्तरदाताओं, सी. एस. ई. पी. डी. एफ. और बी. एच.

ई. एल. को सूचित करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश को संशोधित नहीं किया, जिसका प्रभाव यह था कि जब तक प्रतिवादी के अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक बोली को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा।

5. रिट अपील के निपटारे के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ 25.08.2014 पर अपना अभ्यावेदन भेजा, जिसे अपीलार्थी द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त अस्वीकृति की कानूनी औचित्य पर 2014 की डब्ल्यू. पी. संख्या 26762 की रिट याचिका के माध्यम से सवाल उठाया गया था, जिसमें इसे रद्द करने और मालिक को निविदा को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाने से रोकने की मांग की गई थी। रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, बी. एच. ई. एल., प्रतिवादी संख्या 2 को अनुबंध प्रदान करने वाले 27.09.2014 दिनांकित पत्र की एक प्रति रिकॉर्ड पर लाई गई थी। इसमें प्रतिवादी संख्या 2 के साथ मूल्य वार्ता बैठकों के संबंध में इसका उल्लेख किया गया था। प्रतिवादी नं. 1 ने अपीलार्थी को 01.10.2014 दिनांकित एक पत्र भेजा, जिसमें उसके द्वारा प्रस्तुत बोली के मूल्यांकन के मामले में मनमानेपन, विसंगतियों और तर्क में विसंगतियों और दुर्भावनापूर्ण इरादे पर प्रकाश डाला गया। हालांकि, अपीलार्थी ने दिनांक 10.10.2014 के पत्र द्वारा आई "प्रतिवादी को सूचित किया कि विषय निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और बी. एच. ई. एल. को प्रदान कर दिया गया है।

6. प्रत्यर्थी संख्या 2 को अनुबंध प्रदान करने दिनांक 27.09.2014 के पत्र और प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आक्षेप करने वाले दिनांक 10.10.2014 के पत्र, दोनों को रद्द करने के लिए और निविदा/बोली दस्तावेज के संदर्भ में निविदा के अवार्ड को सख्ती से निर्धारित करने के लिए निगम को निर्देश जारी करने के लिए और प्रतिवादी संख्या 1 और बी. एच. ई. एल., उत्तरदाता संख्या 2 की बोली को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यू. पी. संख्या 27529/2014 दाखिल की गई।



7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुख्य रूप से दिनांकित 30-05-2014 की सलाहकार रिपोर्ट वाली फाइलों में नोटों के अवलोकन के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया और उस आधार पर राय दी कि निविदाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया का संचालन मनमाना, मनमौजी या अनुचित नहीं प्रतीत होता है और बोलीदाताओं की मूल्य बोलियों का मूल्यांकन एक स्वतंत्र सलाहकार द्वारा निविदा अधिसूचना में बताए गए मापदंडों के अनुसार किया गया था, जिसे बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार चुना गया था जो दोनों बोलीदाताओं की जानकारी में था। विद्वान एकल न्यायाधीश का तर्क मूल रूप से सलाहकार की रिपोर्ट पर निर्भर था जिसने निर्धारित किया था कि इसमें प्रतिवादी संख्या 2 एल. आई. था और इसलिए, बी. एच. ई. एल. को एल. आई. के रूप में मानने और अनुबंध देने में निगम का निर्णय न तो मनमाना था और न ही दुर्भावनापूर्ण था।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित, प्रत्यर्थी सं. 1 ने डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपीलों को प्राथमिकता दी। डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी नं. 1 द्वारा उठाई गई विभिन्न याचिकाओं पर ध्यान दिया, जिनमें वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन, मनमानेपन, अनुचित और गैर-पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाना, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सलाहकार की रिपोर्ट का गलत चित्रण और सार्वजनिक हित पर विचार न करना शामिल है।

9. निगम ने अपनी ओर से खंड पीठ के समक्ष तर्क दिया कि प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और अनुबंध का अधिनिर्णय तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्राप्त करने में न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है और कोई भी हस्तक्षेप केवल काम के निष्पादन में देरी करेगा। यह भी आग्रह किया गया कि निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकरण (टी. ए. ए.) ने सबसे कम निविदा को स्वीकार कर लिया था और केवल सबसे कम बोली लगाने वाले के साथ बातचीत की गई थी; कि बोली लगाने वालों को

निर्देश के खंड 25.4 ने बोली लगाने वाले को बोलियों के सार को बदलने की अनुमति नहीं दी थी, हालांकि प्रतिवादी नं. मैंने ब्याज पर कम दर की पेशकश की थी, प्रस्तावित मूल ब्याज दर निविदा शर्तों के अनुसार नहीं थी, क्योंकि खंड 14 (डी) (5) के अनुसार उद्धृत ब्याज की दर तय की जानी चाहिए, जबकि सी. एस. ई. पी. डी. आई. ने ब्याज की निश्चित दर निर्दिष्ट नहीं की थी; कि निविदा की शर्तों, प्रचलित बैंकिंग प्रथा और ऋणदाता द्वारा दिए गए टर्म शीट के अनुसार लिए गए निर्णय में कोई विकृति या मनमानेपन नहीं था; कि सलाहकार की नियुक्ति बोर्ड के संकल्प दिनांक 28.01.2012 के अनुसार की गई थी, जिन्होंने बोली से पहले और बोली के बाद की सभी बैठकों में भाग लिया था और कार्यवृत्त पर सभी पक्षों और सलाहकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और इसलिए, सी. एस. ई. पी. डी. एल. सलाहकार की नियुक्ति के बारे में बहुत जागरूक था।

10. 2<sup>nd</sup> प्रतिवादी ने यहाँ तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 का यह आरोप विश्वसनीयता नहीं था कि डिजाइन कॉन्सोर्टियम के लीडर का मुख्य क्षेत्र था और जहां तक अति महत्वपूर्ण ताप विद्युत परियोजनाओं का संबंध है, उन्हें भारत में कोई अनुभव नहीं है। इसके अलावा काम प्रगति पर था और उन्होंने पर्याप्त राशि खर्च कर ली थी।

11. दोनों पक्षों के विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात् खण्ड पीठ ने जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य (2007) 14 SCC 517 पर भरोसा करते हुए यह अवलोकन किया कि स्वामी की एप्रोच निविदा प्रक्रिया में सही नहीं थी। टी.टी.आई.टी. एक्ट की धारा 10 की स्कीम का पुनः विश्लेषण किया गया और यह निर्धारित किया गया कि निविदा स्वीकृति प्राधिकारी (टी.ए.ए.) की निविदाओं के मूल्यांकन में भूमिका है। टी.टी.आई.टी. एक्ट की धारा 10(6) का संदर्भ देते हुए यह निर्धारित किया गया कि निगम ने इस प्रावधान की पालना नहीं की और यह मामला प्रक्रियात्मक त्रुटि, गलत अप्रोच और मनमानेपन का उदाहरण है। अपीलीय बेंच ने स्टार एन्टरप्राइजेज बनाम महाराष्ट्र शहर व उद्योग विकास निगम लिमिटेड (1990) 3 SCC 280 का संदर्भ देते हुए प्रतिवादी संख्या

1 के प्रतिवेदन को निरस्त करने को उसकी बोली के निरस्त करने का कारण मानने के निगम के निर्णय को स्वीकारने से इंकार कर दिया। इसलिए निर्णय प्रक्रिया को अनुचित और अधिनियम की धारा 10(7) का उल्लंघन माना। आगे यह भी निर्धारित किया कि टेण्डर बुलेटिन में निविदा स्वीकार करने के कारण का अभाव था, निविदा के मूल्यांकन का कथन नहीं था, प्राप्त निविदाओं का कोई तुलनात्मक विवरण नहीं था और उस पर निर्णय टी. टी. आई. टी. अधिनियम की धारा 1ओ और टी. टी. आई. टी. नियमों के नियम 30 (3) के साथ पठित धारा 6 (1) की आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन था। ब्याज घटक और प्रतिबद्धता शुल्क पर, खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि दृष्टिकोण पूरी तरह से मनमाना था और इरादा प्रतिवादी नं. 1, अपनाई गई मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक के अनुरूप और दूसरे को अस्वीकार करने के लिए था। इसने आगे कहा कि मालिक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और लिया गया निर्णय मनमाना, अनुचित, तर्कहीन, पक्षपाती और दुर्भावनापूर्ण था और इससे व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा नहीं होती थी। उक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, खंड पीठ ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और निगम को अपने निष्कर्षों के आलोक में उत्तरदाताओं की मूल्य बोली का मूल्यांकन करने और प्रत्यर्थी सं. 1 का प्रतिवेदन व दस्तावेजों पर गौर करते हुए निष्कर्ष देने के निर्देश दिये और निर्णय के विस्तृत कारणों को दर्ज करने और उन्हें प्रतिवादी सं. 1 को संसूचित करने के भी निर्देश दिये ताकि मैं टी. टी. आई. टी. अधिनियम और टी. टी. आई. टी. नियमों के प्रावधानों और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय की अनुपालना हो सके।

12. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होने के कारण निगम और सफल बोलीदाता ने विशेष अनुमति के माध्यम से अलग-अलग अपीलें की हैं।

13. हमने श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान महान्यायवादी और श्री पराग पी. त्रिपाठी, याचिकाकर्ता-एसएचईएल के विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री सुब्रमण्यम प्रसाद, अपीलकर्ता

निगम के विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री कपिल सिब्बल, प्रतिवादी नं. 1 और श्री श्रीराम पंचू, प्रतिवादी नं. 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील हैं।

14. यह ध्यान देने योग्य है कि सुनवाई के दौरान यह राय दी गई है कि एकमात्र मुद्दा जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि "क्या सलाहकार द्वारा 30 मई, 2014 की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रथम दृष्टया गलत है, जिसमें न्यायिक समीक्षा के मापदंडों के भीतर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।" इस तरह के एकल बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी क्योंकि बी. एच. ई. एल. की ओर से पेश हुए विद्वान महान्यायवादी श्री मुकुल रोहतगी और निगम की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुब्रमण्यम प्रसाद ने प्रस्तुत किया था क्योंकि बी. एच. ई. एल. या आई "प्रतिवादी द्वारा बाद के प्रस्तावों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय, श्री कपिल सिब्बल प्रतिद्वंद्वी पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया था कि सलाहकार की रिपोर्ट ग्राफिक रूप से उजागर करेगी कि प्रतिवादी संख्या 1 एल-1 घोषित किए जाने का अधिकार था, भले ही इसकी न्यायिक समीक्षा के सीमित मापदंडों के भीतर जांच की जाए। न्यायालय ने प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सलाहकार की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश या खंड पीठ द्वारा अन्य मुद्दों पर व्यक्त की गई राय को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

15. अभिलेख पर लाए गए तथ्यों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि निगम ने 30.01.2014 पर आयोजित अपनी बैठक में दोनों बोलीदाताओं पर मूल्य बोलियां खोलने का निर्णय लिया था और उसके बाद दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत तकनीकी विचलन के संबंध में अतिरिक्त प्रभाव वाली वस्तुओं के लिए दोनों पक्षों से पूरक मूल्य बोलियां प्राप्त की गईं और उसके बाद 05.02.2014 पर मूल्य बोलियां खोली गईं। जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है, मूल्य बोलियों का मूल्यांकन सलाहकार द्वारा किया गया था।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मूल्य मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। सलाहकार की रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ जो उनके द्वारा पुनः प्रस्तुत किए गए थे, वे इस प्रकार हैं: -

#### "4.0 मूल्यांकन

##### 4.1 बी. एच. ई. एल.

बी. एच. ई. एल. ने मिस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से वित्त की व्यवस्था की है। उन्हें कुल लागत का 75 प्रतिशत ऋण के रूप में 12.25% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर वित्तपोषित करने की व्यवस्था की जाती है।

संलग्न अनुलग्नक 1 से 5 तक मूल्यांकन के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों की गणना में अपनाई गई कार्यप्रणाली को इंगित करते हैं जैसे! डी. सी.-ऋण, डी. सी.-इक्विटी, आई. डी. सी.-यू. एफ. शुल्क; ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची आदि।

4.2 सी. एस. ई. पी. डी. आई.-ट्रिश सी. एस. ई. पी. डी. आई.-ट्रिश ने मैसर्स आई. सी. बी. सी, चीन से वित्त की व्यवस्था की है। उन्होंने कुल लागत का 85 प्रतिशत ब्याज दर 7.2% प्रति वर्ष पर ऋण के रूप में वित्त की व्यवस्था की है। संलग्न अनुलग्नक 6 से 12 जे. डी. सी.-ऋण, जे. डी. सी.-इक्विटी, आई. डी. सी.-यू. एफ. शुल्क, ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची आदि जैसे मूल्यांकन के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों की गणना में अपनाई गई कार्यप्रणाली को इंगित करते हैं।

5.0 कम लागत का मूल्यांकन किया गया।

			BHEL	CSEPD-TRISHE
			All figures in Rs. (Crores)	All figures in Rs. (Crores)
	Capacity		1320 MW	1320 MW
A	Total EPC cost excluding VAT		7762.977	9207.264
B	EPC Debt	75%	5822.233	7826.174
C	EPC Equity	25%	1940.744	1381.090
D	IDC Debt	12.25%	1295.079	1228.378
E	EPC Debt Including IDC (B + D)		7117.311	9054.552
F	Upfront Fees Including Interest		8.925	801.180
G	Total Debt (E + F)		7126.237	9855.732
H	Interest on Equity	14%	509.597	456.606
I	Total Equity (C+H)		2450.341	1837.695
J	Total Project Cost (G + I)		9576.578	11693.427
K	Total Cost per MW		7.255	8.859
L	PV – Debt		7553.364	8464.318
M	PV – Equity		2809.403	2106.984
N	Total PV		10362.767	10271.302
O	PV Cost per MW		7.851	7.781
P	Loading for Deficiency		10.287	173.229
Q	Total (N+P)		10373.054	10444.531
R	Evaluated Bid Price per MW		7.858	7.913

सलाहकार द्वारा प्रस्तुत "मूल्य मूल्यांकन रिपोर्ट" के पैराग्राफ 4 और 5, जो मैंने ऊपर निकाले हैं, से पता चलता है कि सलाहकार ने भारतीय विद्युत वित्त निगम से बी. एच. ई. एल. द्वारा व्यवस्थित ऋण घटक के लिए केवल 12.25% प्रति वर्ष की ब्याज दर को ध्यान में रखा। सलाहकार ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि बी. एच. ई. एल. का "मूल्यांकन बोली मूल्य" सबसे कम था, बी. एच. ई. एल. द्वारा बाद में दी गई कम दर 12.15 पर ध्यान नहीं दिया।"

16. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि सलाहकार द्वारा मूल्य मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ई. पी. सी. कीमत Rs.9207.264 करोड़ थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 जिसे अनुबंध दिया गया था वह Rs.7762.977 करोड़ थी। इस प्रकार, दो ई. पी. सी. मूल्यों के बीच का अंतर Rs.1444.287 करोड़ है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सलाहकार द्वारा मूल्य मूल्यांकन रिपोर्ट पर इस आधार पर विवाद किया कि उसने (ए) प्रतिबद्धता शुल्क, (बी) जेडीसी अवधि के दौरान प्रबंधन शुल्क पर ब्याज के लिए राशि को गलत तरीके से लोड किया; और (ग) आई. डी. सी. अवधि के दौरान अपनी बोली राशि में गारंटी शुल्क का ब्याज जिसके कारण ब्याज के साथ उद्धृत वित्तीय शुल्क का मूल्यांकन Rs.801.18 करोड़ किया गया था।

17. जहां तक प्रतिबद्धता शुल्क का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का यह कथन कि ऋण की अप्रयुक्त राशि पर प्रतिबद्धता शुल्क लिया जाना था, जिसका अर्थ है कि यदि अपीलकर्ता ऋण राशि निकालने में विफल रहता है, तो केवल प्रतिबद्धता शुल्क लिया जाएगा और इसलिए, इसे जोड़ने के बाद निर्धारण बिना किसी तर्क के किया जाएगा क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने 'वित्तीय लागत के लिए गणना पत्रक' में पूरक बोली प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में 1 करोड़ रुपये का उल्लेख किया था, जो कि उपार्जित निकासी पर प्रति वर्ष 1 प्रतिशत की दर से लिया जाना था और यदि कोई प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, तो प्रतिवादी संख्या 1 को शून्य या शून्य होने का उल्लेख करना चाहिए था। यह दिखाने के लिए कि प्रतिबद्धता शुल्क वित्तीय शुल्क का एक हिस्सा है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने निविदा के तहत बोलीदाताओं को निर्देश के खंड 14 (डी) 6 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जो इस प्रकार है:

"6. वित्तपोषण शुल्क: परियोजना के वित्तपोषण से संबंधित किसी भी नामकरण के सभी वित्तपोषण शुल्क, जिसमें खोज शुल्क, प्रतिबद्धता

शुल्क, व्यवस्था शुल्क, प्रबंधन शुल्क, अग्रिम शुल्क, सिंडिकेशन शुल्क, सेवा शुल्क, गारंटी शुल्क, अन्य शुल्क और कर, यदि कोई हो, शामिल हैं, वित्तपोषण अवधि पत्रक में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए जाने चाहिए। ऋण की अवधि के दौरान वित्तपोषण शुल्क में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है।

3.37 "वित्तपोषण लागत" का अर्थ है परियोजना के वित्तपोषण से संबंधित किसी भी नामकरण के सभी वित्तपोषण शुल्क, जिसमें खोजकर्ता शुल्क, व्यवस्था शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, प्रबंधन शुल्क, अग्रिम शुल्क, समन्वय शुल्क, सेवा शुल्क, गारंटी शुल्क, अन्य शुल्क और कर, यदि कोई हो, शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।"

18: इस समय हम धारा 2 के खंड 3.37 का भी उल्लेख कर सकते हैं जो अनुबंध के सामान्य नियमों और शर्तों से संबंधित है। यह "वित्तपोषण लागत" को निम्नानुसार परिभाषित करता है:-

"वित्तपोषण लागत" का अर्थ परियोजना के वित्तपोषण से संबंधित किसी भी नामकरण के सभी वित्तपोषण शुल्क हैं, जिनमें खोजकर्ता शुल्क, प्रबंधक शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, प्रबंधन शुल्क, अग्रिम शुल्क, समन्वय शुल्क, सेवा शुल्क, गारंटी शुल्क, अन्य शुल्क और कर, यदि कोई हो, शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

19. खंड 14 जो एक बाध्यकारी ऋण वित्तपोषण अवधि पत्रक की शर्तों से संबंधित है, जिसे पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसमें इस प्रकार लिखा है:-

"बाध्यकारी ऋण वित्तपोषण अवधि पत्रक के लिए 14 शर्तें।



बोलीदाता ऋण वित्तपोषण के लिए ऋणदाता के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करेगा जो परियोजना के लिए वित्तपोषण प्रदान करने और भुगतान खंड की शर्तों के अनुसार टेंगेडको द्वारा प्रमाणित बिलों के आधार पर सीधे बोलीदाता को भुगतान करने के लिए सहमत होगा।

ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के अपने प्रस्ताव के साथ बोलीदाता द्वारा समझौता ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा।

बोलीदाता आशय पत्र (एल. ओ. आई.) की तारीख से 4 (चार महीने) के भीतर आवश्यक वित्तपोषण की व्यवस्था करने और परियोजना के वित्तीय समापन को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।

a. बोलीदाता और ऋणदाता उचित परिश्रम के अधीन ऋणदाता से ऋण वित्तपोषण व्यवस्था के प्रस्ताव में की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक संयुक्त वचन प्रस्तुत करेंगे।

टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ सफल बोलीदाता को ऋण वित्तपोषण के प्रसंस्करण के लिए ऋणदाता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

1. टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ की रूपरेखा।

2 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए टेंगेडको की लेखा परीक्षित तुलनपत्र

3. इस परियोजना के लिए कोयले की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए टेंगेडको और एम. एम. टी. सी. के बीच समझौता ज्ञापन हुआ।

4. बिजली की बिक्री के लिए शुल्क आदेश।

## 5. डी. पी. आर. बी. की प्रति।

यह समझा जाएगा कि वित्तपोषण अवधि पत्रक बोलीदाता और ऋणदाता द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना के प्रारंभिक मूल्यांकन पर आधारित होगा जो परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर खुद को संतुष्ट करते हैं। यह समझा जाएगा कि बोलीदाता को अनुबंध का अवाई वित्तपोषण अवधि पत्रक में दिए गए नियमों और शर्तों के आधार पर सफल वित्तीय समापन पर निर्भर है और यदि वह बोलीदाता या ऋणदाता के कारण वित्तीय समापन नहीं होता है या ऋणदाता द्वारा परियोजना से निकासी की स्थिति में, बोलीदाता प्रतिभूति जमा को जब्त कर लेगा। टर्म शीट वित्तपोषण की सभी भौतिक शर्तों के साथ पूर्ण और पूर्ण होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

1. ऋण राशि: कुल ई. पी. सी. लागत का कम से कम 75 प्रतिशत + निर्माण और वित्तपोषण लागत के दौरान 100% ब्याज
2. ऋण की मुद्रा: आई. एन. आर./यू. एस. डी./यूरो या उसका संयोजन।
3. ऋण की अवधि: ऋण के पहले आहरण की तारीख से आई या दूसरी इकाई के सीओडी से 6 महीने तक, जो भी बाद में हो और उसके 15 साल बाद।
4. ब्याज की दर।
5. बाड़ लागत को ध्यान में रखते हुए ऋण की पूरी अवधि तक ब्याज की निश्चित दर।

6. वित्तपोषण शुल्क: परियोजना के वित्तपोषण से संबंधित किसी भी नामकरण के सभी वित्तपोषण शुल्क, जिसमें खोज शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, व्यवस्था शुल्क, प्रबंधन शुल्क, अग्रिम शुल्क, सिंडिकेशन शुल्क, सेवा शुल्क, गारंटी शुल्क, अन्य शुल्क और कर, यदि कोई हो, शामिल हैं, वित्तपोषण अवधि पत्रक में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए जाने चाहिए। ऋण की अवधि के दौरान वित्तपोषण शुल्क में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है।

7. ड्रॉ डाउन अनुसूची के लिए नियम और शर्तें।

8. किश्त, ब्याज और वित्तपोषण शुल्कों के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन: किश्त, ब्याज और वित्तपोषण शुल्कों के पुनर्भुगतान के लिए टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ का सभी नकद बहिर्वाह दायित्व ऋण की पूरी अवधि के लिए INR (पूरी तरह से हेज) में होना चाहिए और पुनर्भुगतान बाद की इकाई के COD की तारीख से 6 महीने के बाद ही शुरू होगा।

9. पुनर्भुगतान अवधि: आई. डी. सी. के बाद 15 वर्ष और 60 समान तिमाही किश्तों में स्थगन

10। परियोजना नकद प्रवाह और किश्त पुनर्भुगतान विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह वित्तपोषण प्रस्ताव का हिस्सा होगा। बोलीदाता परियोजना गतिविधियों की आपूर्ति और निर्माण अनुसूची से मेल खाने के लिए वित्त की निकासी अनुसूची का संकेत देगा।

11. समानता की आवश्यकताएँ और संबंधित करार।

12. प्रतिभूति: प्रतिभूति के विरुद्ध निम्नलिखित को टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सरकारी गारंटी

13. टर्म शीट की वैधता अवधि बोली की वैधता के साथ-साथ समाप्त हो जाएगी।"

20. खंड 14 (घ) 6 की व्याख्या के संबंध में प्रत्यर्थी का रुख यह है कि यह केवल सभी शुल्कों की रूपरेखा तैयार करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एल. एल. निर्धारित करने के लिए बोली का मूल्यांकन करने के लिए इस तरह के प्रत्येक शुल्क को भरा जाना है और इस तरह के मूल्यांकन के लिए कोई प्रतिबद्धता शुल्क नहीं लिया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि प्रतिबद्धता शुल्क पर ब्याज लोड करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है

21. जैसा कि पहले कहा गया है, सलाहकार की रिपोर्ट की शुद्धता से संबंधित मुद्दे को तथ्यात्मक अंक प्राप्त करने में न्यायिक समीक्षा की सीमित शक्ति के दायरे में निर्णय और जांच की जानी चाहिए। खंड पीठ ने विवादित फैसले में एल. एल. की पहचान में अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। इसने अपने दिनांकित 19.8.2014 के आदेश का उल्लेख किया है जिसमें एल. प्रतिवादी को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया था। विवादित आदेश में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि उस समय निगम ने कभी यह नहीं माना था कि निविदा को अंतिम रूप दिया गया था। इसने डिवीजन बेंच के पहले के आदेश का उल्लेख किया है कि अभ्यावेदन पर विचार किया जाना चाहिए और तब तक बोली को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। इसने निगम के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक के 20 तारीख के पत्र का उल्लेख किया है। 7.2014 और राय दी कि यह तथ्य का गलत कथन प्रतीत होता है।

22. यह कहा जाए कि खंड पीठ ने दो प्रश्न उठाए हैं:-

(i) क्या अपीलार्थी द्वारा दिया गया ब्याज अस्पष्ट है; और

(ii) क्या ब्याज को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.2 प्रतिशत करने को स्वीकार किया जाना चाहिए।

23. उक्त मुद्दे पर विचार करते हुए, खंड पीठ ने निविदा पर निर्णय के बारे में बताते हुए निविदा बुलेटिन में प्रकाशन का उल्लेख किया है:-

"1. निविदा का नाम मुख्य अभियंता/सिविल/परियोजना और पर्यावरण, आमंत्रित अधिकारी, जे. डी. फ्लोर, एन. पी. के. आर. आर. माल इगाई, 144, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002।

2. क) परियोजना का नाम/खरीद और कार्यों का विवरण: एकल ई. पी. सी. सह ऋण वित्त आधार के तहत मौजूदा एन. सी. टी. पी. एस. के ऐश डाइक में 2 गुणा 660 मेगावाट की एन्नोर एस. ई. जेड. सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की स्थापना। वायलुरविलेज, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु।

नंबर	विवरण	निविदा मूल्य	निविदा पर निर्णय
1	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल हाउस, सिरिफोर्ट, नई दिल्ली-110 049	7840.087 करोड़ और ऋणदाता: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ब्याज दर: 12.25%	इस काम के लिए प्राप्त चार बोलियों में से और योग्य दो बोलीदाताओं में से, सबसे कम बोली लगाने वाले यानी मैसर्स भेल के साथ बातचीत की गई और बातचीत

	<p>कान्सोरिटम ऑफ सेण्ट्रल साउदर्न चाइना इलेक्ट्रीक पॉवर डिजायन मैसर्स ट्रीशे, 668, मिन्ज रोड, उगान, चाइना - 430071</p>	<p>9716.5974 करोड़ और ऋणदाता: औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बैंक, चाइना, ब्याज दर: 7.2% (USD@59.26 एस बी आई बिल सेलिंग दर)</p>	<p>की गई। 7788 करोड़ रुपये, 12.15% पर ब्याज की दर को मुख्य अभियंता/ परियोजनाओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इस कार्यालय के मुद्दे Lr. No. CE /P /SE / M/ EE10 / E/ File 2x660 मेगावाट एन्नोर एस. ई. जेड. एस. टी. के माध्यम से जारी निविदा को स्वीकार करने का आदेश दिया गया। पी. पी./डी. संख्या 60/डी. टी.</p>
--	--	---	--

अंत में, मैसर्स बी. एच. ई. एल., नई दिल्ली ने रुपये के लिए बोली की पेशकश की। टी. टी. एल. के मुख्य अभियंता/परियोजना/चेन्नई द्वारा 7788 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए और निविदा स्वीकार करने का आदेश इस अधिकारी Lr.No.CE/P/SE एम./ई. ई.-10/ई./फाइल. 2x660 एम. डब्ल्यू. एन्नोर एस. ई. जेड. एस. टी. पी. पी./डी. नं. 60/ दिनांकित 27.09.2014 द्वारा जारी किया गया।"

24. इसके बाद, खंड पीठ ने निम्नानुसार अभिलिखित किया है:-

"31.3 यद्यपि यह अपीलार्थी की याचिका है कि उनके द्वारा प्रति वर्ष 7.2- 7.5% की निश्चित दर या एल. आई. बी. ओ. आर. अस्थायी दर उद्धृत की गई है, यह विद्वान महाधिवक्ता का मामला है कि बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के खंड 12.1 में कहा गया है कि ब्याज निश्चित दर पर उद्धृत किया जाना है और यह परिवर्तन के अधीन नहीं है, और चूंकि उद्धृत ब्याज परिवर्तनीय है, इसलिए बोली का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

31.4 अभिलेखों से यह देखा गया है कि बाद में, प्रथम प्रत्यर्थी के एक प्रश्न के आधार पर, अपीलार्थी ने पुष्टि की थी कि यह 7.7% की निश्चित ब्याज दर होगी। पुनर्भुगतान अनुसूची में भी इसकी पुष्टि की गई थी और सलाहकार द्वारा अपनी दिनांकित 30.5.2014 रिपोर्ट में इसी ब्याज दर को ध्यान में रखा गया था। उन्होंने ब्याज की दर में कोई गलती नहीं पाई। यह ध्यान देने योग्य है कि कार्यकाल पत्रक जुलाई, 2013 के दौरान प्रस्तुत किया गया था और निविदा का मूल्यांकन वर्ष 2014 में किया गया था। ब्याज की दर में अस्पष्टता का विवाद हमें आकर्षित नहीं करता है। जब सलाहकार की रिपोर्ट दिनांक 30.5.2014 को मूल्यांकन के उद्देश्य से टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो इसे सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए, हालांकि हमें सलाहकार की रिपोर्ट दिनांक 30.5.2014 पर आरक्षण है। वहाँ है; अतः 7.7 प्रतिशत पर उद्धृत ब्याज दर में कोई अस्पष्टता नहीं है।

31.5 दूसरा मुद्दा ब्याज दर में कमी से संबंधित है। यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी और टेंगेडको के बीच विभिन्न बैठकें हुईं। विद्वान

महाधिवक्ता का कहना है कि सलाहकार की नियुक्ति 21 वीं बोर्ड बैठक के आधार पर की गई थी और सलाहकार ने बोली से पहले और बोली के बाद की सभी बैठकों में भाग लिया और बी. एच. ई. एल. और अपीलकर्ता सहित सभी पक्षों द्वारा कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी सलाहकार की नियुक्ति और उसकी भूमिका से अवगत था। यह केवल इस तथ्य को मजबूत करता है कि दोनों बोलीदाताओं के बीच परामर्श की श्रृंखला रही है। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी ने आंतरिक जानकारी पर कार्रवाई की, उपरोक्त विद्वान महाधिवक्ता के रुख से ध्वस्त हो जाता है। इस आक्षेप का कोई आधार नहीं है

31.6 ब्याज की दर में कमी के मुद्दे पर आते हुए, प्रचलित बाजार दर को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार के मुकदमे से पहले भी 5.6.2014 पर ब्याज की दर को 7.2% से घटाकर 6.2% करने की पेशकश की। जब अपीलार्थी द्वारा ऐसा प्रस्ताव दिया गया था तो अधिनियम की धारा 10 (6) के संदर्भ में निविदा स्वीकार नहीं की गई थी। पुनर्कथन करने के लिए, पहले जो हुआ है वह यह है कि 2014 की डब्ल्यू. पी. संख्या 19247 में रिट याचिका 17.7.2014 को दायर की गई थी। 5.6.2014 पर दिए गए प्रस्ताव के बाद। पहला अंतरिम आदेश 18.7.2014 पर पारित किया गया था। दूसरा अंतरिम आदेश 31.7.2014 पर पारित किया गया था। डिवीजन बेंच ने 19.8.2014 पर एक आदेश पारित किया। उस समय, टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ द्वारा कभी भी यह बयान नहीं दिया गया था कि LI की पहचान की गई थी और चर्चा चल रही थी। हमने यह भी स्पष्ट



रूप से कहा है कि टैंगेडको के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का बयान कि निविदा को अंतिम रूप देते समय निदेशक मंडल द्वारा अपीलकर्ता के अभ्यावेदन पर विधिवत विचार किया जाएगा और निविदा विनिर्देशों के अनुसार और टी. टी. आई. टी. अधिनियम और टी. टी. आई. टी. नियमों के प्रावधानों का पालन करते हुए उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

31.7 इसलिए ब्याज दर में कमी से संबंधित मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए था। हमारा यह तर्क इस तथ्य पर भी आधारित है कि हमने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि तीसरे प्रतिवादी का पता टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ के कथन के अनुसार या विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष के अनुसार 2.6.2014 पर L1 के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। एक बार जब एल1 की कोई पहचान नहीं हो जाती है, तो टैंगेडको अपने दिनांकित 5.6.2014 के प्रस्ताव में अपीलार्थी और दिनांकित 27.6.2014 के तीसरे प्रतिवादी दोनों की ब्याज दर में कमी पर विचार करने के लिए बाध्य है, जिससे ब्याज की दर 12.25% से घटकर 12.15 प्रतिशत हो जाएगी।

31.8 अन्यथा भी, बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के खंड 25.3 के तहत शक्ति के आधार पर, जिसमें कहा गया है कि "खरीदार के पास टैंगेडको के सर्वोत्तम हित में इस विनिर्देशन की किसी भी शर्त में डील देने या उसे माफ करने का अधिकार सुरक्षित है", टैंगेडको अपीलकर्ता और तीसरे प्रतिवादी द्वारा दी गई ब्याज की ऐसी कम दर पर विचार कर सकता था।"

25. प्रतिबद्धता शुल्क के संबंध में, डिवीजन बेंच का विश्लेषण उल्लेख करने योग्य है:-

"यह स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रतिबद्धता शुल्क केवल ऋण के रद्द किए गए हिस्से पर है। इसके अलावा, ड्रॉ डाउन अनुसूची के अनुसार भी, शुल्क का भुगतान केवल तभी किया जाना है जब ऋण राशि। 81h, 30th और 42 "d महीने तक नहीं निकाली जाती है। इसके अलावा, अपीलार्थी ने दिनांकित 13.6.2014, 16.6.2014 और 17.6.2014 पत्रों में स्पष्ट किया कि प्रतिबद्धता शुल्क केवल अप्रयुक्त क्रेडिट लाइन पर है और यदि ऋण राशि का पूरी तरह से उपयोग ड्रॉ डाउन अनुसूची के अनुसार किया जाता है तो कोई प्रतिबद्धता शुल्क नहीं होगा। अपीलार्थी द्वारा भेजे गए इन सभी अभ्यावेदनों पर टैंगेडको द्वारा विचार नहीं किया गया था, इसके बावजूद कि इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इस पर विचार करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश दिया गया था। यह दृष्टिकोण में मनमानेपन का एक स्पष्ट मामला है और इसका उद्देश्य अपीलार्थी को बाहर करना है। टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. का यह कार्य और कुछ नहीं बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया में एक के अनुरूप होने और दूसरे को अस्वीकार करने के लिए दुर्भावनापूर्ण मामला है।"

26. सलाहकार की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, खंड पीठ ने आगे कहा है:-

"33.3 सलाहकार की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलकर्ता और तीसरे प्रतिवादी की बोली के बीच का अंतर लगभग 71 करोड़ रु. इस मामले में, यदि 36 महीने की निर्माण अवधि के लिए Rs.156.184 करोड़ का प्रतिबद्धता शुल्क या प्रबंधन शुल्क और गारंटी शुल्क पर ब्याज

अपीलार्थी पर नहीं लगाया जाता है, तो इसका यह तय करने पर असर पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी सबसे कम बोली है। यह मानते हुए कि सलाहकार की रिपोर्ट का कोई मूल्य है, प्रासंगिक सामग्री पर विचार किए बिना ऐसी रिपोर्ट का कोई उपयोग नहीं है। अभ्यावेदन और अतिरिक्त विवरणों/दस्तावेजों पर ध्यान दिए बिना इन आंकड़ों को जोड़ने का दृष्टिकोण, इसलिए, मनमाना और पूर्वाग्रह में दूषित है। यह डिवीजन बेंच के फैसले के साथ-साथ मुकदमे के पहले दौर में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों का उल्लंघन है।

27. और फिर से: -

"दो निविदाकारों के संबंध में वित्तीय प्रभाव सलाहकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। मुद्दा यह है कि कारकों का क्या अर्थ है और यह बोली को कैसे प्रभावित करता है। हम पाते हैं कि जे. डी. सी. अवधि के दौरान प्रबंधन शुल्क और गारंटी शुल्क पर ब्याज के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्भुगतान अनुसूची सलाहकार द्वारा एक स्वीकृत दस्तावेज है। यदि इसके अलावा और कुछ भी भुगतान नहीं किया जाना है और इसे स्पष्ट शब्दों में प्रतिनिधित्व के दौरान स्पष्ट किया जाता है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि इस राशि को लागत में कैसे शामिल किया जा सकता है, जबकि इसका कोई निहितार्थ नहीं है। जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है, सलाहकार को इस मुद्दे में वित्तीय प्रभावों पर अभ्यावेदन और अन्य दस्तावेजों पर विचार करने का लाभ नहीं मिला। इसलिए उनकी राय प्रासंगिक दस्तावेज/प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं है। यह हमने अभिनिर्धारित किया है कि मुकदमे के पहले दौर में विद्वान एकल न्यायाधीश के

आदेश के अनुरूप नहीं है, जिसकी पुष्टि खंड पीठ ने की थी। इस तरह के कारक को रोकना और अपीलार्थी की बोली को लोड करने वाले सलाहकार से मूल्यांकन प्राप्त करना स्पष्ट रूप से पक्षपात का मामला है। यह एक अनुचित दृष्टिकोण और एक अनुचित इशारा है जो पारदर्शी कोमलता की भावना को कुचल देता है।

33.6 इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि पहले प्रतिवादी ने प्रबंधन शुल्क और गारंटी शुल्क पर गलती से ब्याज जोड़ा था, जब कोई नहीं है और कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता नहीं है। एक बार जब अपीलार्थी प्रतिनिधित्व में स्पष्ट शब्दों में संकेत दे देता है कि इसे कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, डिवीजन बेंच के आदेश के आलोक में, जिसे टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. ने अपीलार्थी की बोली पर विचार करने के लिए स्वीकार कर लिया था, तो पहले प्रतिवादी को इस राशि को सलाहकार की रिपोर्ट के आधार पर लोड नहीं करना चाहिए था। यदि दोनों बोलीदाताओं के साथ निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांत के आधार पर व्यवहार किया जाना है, तो पहली प्रत्यर्थी के निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकरण को पूरी निष्पक्षता के साथ इस राशि को बाहर कर देना चाहिए था। यह आवश्यक हो जाता है क्योंकि संपूर्ण निविदा का परीक्षण व्यापक जनहित पर किया जाता है, अर्थात्, परियोजना का समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन जहां निर्णय लेने में लागत एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। कल्याणकारी राज्य में, सार्वजनिक प्राधिकरण मनमाने ढंग से ऐसे प्रस्ताव को खारिज करने का निर्णय नहीं ले सकता है, जिस पर वे न्यायिक कार्यवाही के दौरान विचार करने के लिए सहमत हुए, जिसका

हमने ऊपर उल्लेख किया है। इन कारकों, अर्थात्, प्रबंधन शुल्क और गारंटी शुल्क पर ब्याज जोड़ने, को अपीलार्थी की बोली पर विचार करने के उद्देश्य से छोड़ना होगा, अन्यथा, यह अनुचितता और तर्कहीनता के दुष्प्रभाव से पीड़ित होगा।"

28. अंततः, यह इस प्रकार निर्देशित किया गया:- "टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ को उपरोक्त हमारे निष्कर्षों के आलोक में, तीसरे प्रतिवादी की बोली के साथ-साथ अपीलकर्ता की मूल्य बोली का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है और सभी आवश्यक मापदंडों और अपीलकर्ता द्वारा अपने विभिन्न अभ्यावेदनों में प्रस्तुत स्पष्टीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है, जैसा कि एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 31.7.2014 के आदेश में और डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 19.8.2014 के अपने आदेश में नए सिरे से निर्देश दिया गया है।

29. इस न्यायालय के समक्ष, सलाहकार की रिपोर्ट की आई "प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार आलोचना की जाती है:-

"2 सलाहकार ने सी. एस. ई. पी. डी. आई. की बोली के संबंध में कथित 'ब्याज सहित अग्रिम शुल्क' की गणना में निम्नलिखित त्रुटियां की हैं:

त्रुटि 1: प्रतिबद्धता शुल्क शामिल त्रुटि

2: (ए.) पर गणना की गई और जमा की गई ब्याज गारंटी शुल्क,

(बी.) प्रबंधन शुल्क और

(सी.) 36 महीने की निर्माण अवधि के दौरान प्रतिबद्धता शुल्क, यानी

आई. डी. सी. (निर्माण के दौरान ब्याज)

2.4 5 आइटम एफ-'ब्याज सहित अग्रिम शुल्क' में, सलाहकार ने बी. एच. ई. एल. को Rs.8.925 करोड़ और सी. एस. ई. पी. डी. आई. को रु. 801.180 करोड़। इस रुपये का विभाजन। 801.180 सलाहकार की रिपोर्ट में करोड़ इस प्रकार हैं:

ए. गारंटी शुल्क रु. 371.743 करोड़

बी. प्रबंधन शुल्क

सी. प्रतिबद्धता शुल्क

डी. ए, बी, सी पर 36 महीने के लिए ब्याज (रु. 127.613 करोड़) रु. 117.393 करोड़ रु. 156.184 करोड़

ई. 37 वें से 42 वें महीने तक का ब्याज 1.5 5 रुपये, ए, बी और सी पर 860 करोड़ (रु. 28.247 करोड़) कुल रु. 801.180 करोड़

2.4.1 ए. और बी. प्रविष्टियों पर कोई मुद्दा नहीं है। ऊपर 2.4.2 यह मुद्दा उपरोक्त प्रविष्टियों ग. और घ. के संबंध में है। 2. 4. 3. ग. के संबंध में, नीचे बताए गए कारणों से कोई प्रतिबद्धता शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

2.4.4 घ. के संबंध में, नीचे बताए गए कारणों से गारंटी शुल्क और प्रबंधन शुल्क पर 36 महीने की निर्माण अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं लगाया जा सकता है। प्रतिबद्धता शुल्क पर ब्याज का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सी. एस. ई. पी. डी. आई. की बोली के मूल्यांकन के लिए कोई प्रतिबद्धता शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

2.4.5 e. उपरोक्त कम हो जाएगा क्योंकि यह सी. और डी. पर निर्भर करता है।

2.5 यदि सलाहकार ने प्रतिबद्धता शुल्क और गारंटी शुल्क पर ब्याज को शामिल नहीं करके सी. एस. ई. पी. डी. आई. की मूल्य बोली का सही मूल्यांकन किया था। 36 महीने की निर्माण अवधि के लिए प्रबंधन शुल्क और प्रतिबद्धता शुल्क, फिर सी. एस. ई. पी. डी. आई. रुपये से एल. आई. होगा। 171.600 करोड़। न तो टेंगेडको और न ही भेल ने इस तथ्य पर विवाद किया है।

X X X X

2.7 सलाहकार ने प्रतिबद्धता शुल्क को अग्रिम शुल्क के साथ भ्रमित कर दिया है। प्रतिबद्धता शुल्क, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक आकस्मिक शुल्क है जो देय है यदि निर्धारित निकासी नहीं होती है। ऋणदाता द्वारा बिना किसी आकस्मिकता के एक निश्चित शुल्क के रूप में एक अग्रिम शुल्क लगाया जाता है। यह पी. एफ. सी. (बी. एच. ई. एल. के ऋणदाता) द्वारा दिनांकित 30-04-2015 पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है जिसमें प्रतिबद्धता शुल्क और अग्रिम शुल्क को अलग-अलग विकल्पों के रूप में दिखाया गया है। सलाहकार ने बी. एच. ई. एल. को अग्रिम शुल्क के साथ लोड किया है। सलाहकार ने गलती से प्रतिबद्धता शुल्क को सी. एस. ई. पी. डी. आई. के लिए एक अग्रिम शुल्क के रूप में माना है और वास्तव में आइटम एफ में लेबल अग्रिम शुल्क लागू किया है।"

30. प्रतिबद्धता शुल्क के संबंध में, विभिन्न वित्तीय बारीकियों को बताया गया है। हम समझते हैं कि उनमें से कुछ को पुनः प्रस्तुत करना उचित है:-

"2.8.3 जब निर्धारित धनराशि निकाली जाती है, तो सहमत ब्याज देय होता है। जब निर्धारित धनराशि नहीं ली जाती है, तो ब्याज देय नहीं होता है, बल्कि इसके बजाय जो राशि नहीं ली जाती है, उस पर प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

2.8.4 सी. एस. ई. पी. डी. आई. की टर्म शीट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऋण के रद्द किए गए हिस्से पर प्रतिबद्धता शुल्क देय है।

2.8.5 'उपार्जित आहरण' शब्द उपार्जित और आहरण के लिए उपलब्ध राशि को संदर्भित करता है, लेकिन आहरण के लिए नहीं।

2.8.6 इसलिए प्रतिबद्धता शुल्क केवल एक आकस्मिक शुल्क है जो तब लगाया जा सकता है जब धन निकासी अनुसूची के अनुसार नहीं निकाला जाता है। यह उधारकर्ता टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. द्वारा चूक की स्थिति में जुर्माना की प्रकृति में अधिक है और टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. द्वारा देय है। मूल्य बोली के मूल्यांकन के लिए इसे परियोजना लागत में नहीं जोड़ा जा सकता है।

x x x x

2.8.8 पुनर्भुगतान अनुसूची 12 वर्षों के लिए वित्तीय बंद होने की तारीख के 43 वें महीने से शुरू होने वाली 48 समान तिमाही किश्तों (ई. क्यू. आई.) के रूप में टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. द्वारा भुगतान की जाने वाली पूरी राशि निर्धारित करती है। यदि मूल्य बोली का मूल्यांकन करने के लिए एक दस्तावेज को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वह यह पुनर्भुगतान अनुसूची है। पुनर्भुगतान अनुसूची



मूल्य बोली का हिस्सा है और बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टेंगेडको द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को सीमित करती है। पुनर्भुगतान अनुसूची में उल्लिखित राशि के अलावा एक भी रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। .

2.8.9 पुनर्भुगतान अनुसूची में ई. क्यू. आई. रुपये के आंकड़े पर आधारित है। 15, 038.2914 करोड़, जिसमें रु। 5025.3628 करोड़ रुपये की शुद्ध ऋण राशि पर करोड़। 1 0,012.9286 करोड़। इस शुद्ध ऋण राशि के घटक इस प्रकार हैं:

ए. ऋण राशि

(9709.3822 करोड़ रुपये की कुल 8252.9748 Rs.

ई. पी. सी. लागत का 85 प्रतिशत)

बी. 36 महीने की निर्माण अवधि के दौरान 896.2032 Rs.

उपरोक्त ऋण राशि पर 7.2 प्रतिशत

प्रति वर्ष का ब्याज।

सी. गारंटी शुल्क 392.0163 Rs.

डी. प्रबंधन शुल्क अधिस्थगन अवधि का ब्याज 123.7946 Rs.

37 घंटे से 42 डिग्री प्रति माह के लिए

(कुल ए, बी, सी और डी पर 6 महीने के लिए

7.7 प्रतिशत प्रति माह ब्याज) 347.9396 Rs.

**कुल Rs.10,012.9286**

\*सी. एस. ई. पी. डी. आई. द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोली रु. 9709.3822 करोड़ और उपरोक्त गणनाएँ उसी आधार पर थीं। हालांकि इस राशि में से स्वीकृत स्थिति टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. द्वारा 509.339 करोड़ रुपये की अनुमति नहीं दी गई थी और मूल्य बोली Rs.9207.264 करोड़ पर पहुंची थी। सलाहकार ने सी. एस. ई. पी. डी. एल. की बोली का भी 9207.264 करोड़ रुपये मूल्यांकन किया है।"

31. 36 महीनों की निर्माण अवधि के दौरान गारंटी शुल्क और प्रबंधन शुल्क पर कोई ब्याज नहीं और प्रतिबद्धता शुल्क पर कोई ब्याज नहीं होने के संबंध में, प्रत्यर्थी का रुख विभिन्न विभागों में रखा गया है। हम प्रासंगिक आधारों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं: -

"2.9.1 सी. एस. ई. पी. डी. आई. की मूल्य बोली के मूल्यांकन के लिए सलाहकार को 36 महीने की निर्माण अवधि के दौरान गारंटी शुल्क और प्रबंधन शुल्क पर ब्याज नहीं देना चाहिए था।

2.9.2 ऊपर दी गई समान पुनर्भुगतान अनुसूची गणना से पता चलता है कि 36 महीनों की निर्माण अवधि के दौरान गारंटी शुल्क और प्रबंधन शुल्क पर कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा है और यह उस राशि का हिस्सा नहीं है जिसे टैंगेडको को चुकाना है। पुनर्भुगतान अनुसूची में उल्लिखित राशि के अलावा एक भी रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। 36 महीनों की निर्माण अवधि के दौरान देय एकमात्र ब्याज मूल ऋण राशि (ई. पी. सी. लागत का 85 प्रतिशत) पर 7.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गई ब्याज है, न कि

गारंटी शुल्क और प्रबंधन शुल्क जैसी किसी अन्य राशि पर। सी. एस. ई. पी. डी. आई. द्वारा अपनी मूल्य बोली में प्रस्तुत निर्माण के दौरान ब्याज के लिए विशिष्ट गणना पत्रक में यह स्पष्ट किया गया है।

2.9.4 सी. एस. ई. पी. डी. आई. द्वारा प्रस्तुत टर्म शीट में टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. द्वारा भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक शुल्क और उन परिस्थितियों को रेखांकित किया गया है जिनमें वे देय हैं। इस अनुबंध की प्रकृति में, प्रभार्य वस्तुओं का उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि उन वस्तुओं का जो प्रभार्य नहीं हैं। अनुबंध का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि बोली लगाने वाला टेंगेडको से क्या शुल्क ले रहा है।

2.9.5 सी. एस. ई. पी. डी. आई. की टर्म शीट में प्रबंधन शुल्क और सिनोसुर पुनर्बीमा (गारंटी शुल्क) का उल्लेख किया गया है। 36 महीनों की निर्माण अवधि के लिए प्रबंधन शुल्क और गारंटी शुल्क पर ब्याज का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

2.9.6 जहां तक प्रतिबद्धता शुल्क पर ब्याज का सवाल है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि सी. एस. ई. पी. डी. एल. की बोली का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिबद्धता शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

32. प्रत्यर्थी ने यह भी कहा है कि सलाहकार सी. एस. ई. पी. डी. आई. बोली पर 36 महीने की निर्माण अवधि के दौरान प्रतिबद्धता शुल्क और उस पर ब्याज और गारंटी शुल्क और प्रबंधन शुल्क पर ब्याज के मूल्यों को लोड करने में सही नहीं था, क्योंकि वह खंड 14.d.6 केवल यह बताता है कि वित्तपोषण शुल्क का विवरण वित्तपोषण अवधि पत्रक में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए और यह नहीं कहता है कि

इसे पी. डी. सी. ई. मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए; कि अवधि पत्रक में प्रतिबद्धता शुल्क का संदर्भ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह केवल ऋण के रद्द किए गए हिस्से पर है; कि शुल्क का भुगतान केवल तभी किया जाना है जब ऋण राशि 18 'एच, 30' एच और 42 'डी द्वारा नहीं खींची जाती है। सी. एस. ई. पी. डी. आई. की मूल्य बोली के मूल्यांकन के लिए विवादित राशि को लोड नहीं किया है। यह भी मत है कि दाखिल की गई तुलना पत्रक के अवलोकन पर यह संकेत मिलेगा कि यदि मूल्यांकन सही ढंग से किया जाता है तो सी. एस. ई. पी. डी. आई. Rs.171600 करोड़ से एल. आई. है। इसके अलावा, प्रतिवादी ने अन्य आधार भी उठाए हैं जिनका हमें विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

33. सलाहकार की रिपोर्ट के समर्थन में निगम ने कहा है कि प्रथम प्रतिवादी का रुख है कि शुद्ध ऋण राशि प्रत्यर्थी सं। में इस बात का कोई विवरण नहीं देता कि उक्त आंकड़ा कैसे प्राप्त किया गया है; कि कोई भी उक्त पुनर्भुगतान अनुसूची के केवल अवलोकन से यह पता नहीं लगा सकता है कि क्या प्रतिवादी नं। में शुद्ध ऋण राशि में प्रतिबद्धता शुल्क के घटक को शामिल किया है; कि प्रत्यर्थी को एल. एल. बोलीदाता के रूप में पोस्ट फैक्टो विवाद के रूप में घोषित नहीं किया गया है, अब कहते हैं कि प्रतिबद्धता शुल्क मूल्यांकन के लिए नहीं लिया जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने स्वयं मूल्य बोली में विभाजित विवरण के साथ Rs.164.702 करोड़ के लिए प्रतिबद्धता शुल्क का हवाला दिया है और उपरोक्त पोस्ट फैक्टो विवाद निष्पक्षता और न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है; कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 एल. 1 बन जाता, तो वे इस बात पर जोर देते कि प्रतिबद्धता शुल्क एक वित्तीय शुल्क होने के कारण ऋण का हिस्सा है और इसलिए ऋणकर्ता द्वारा देय है, अर्थात्, निगम प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उनकी मूल्य बोलियों के अनुसार।।; कि उत्तरदाता नं। मेरा मूल्यांकन एल. आई.

के रूप में नहीं किया गया था, एक तर्क दिया गया है कि प्रतिबद्धता शुल्क को सार्वभौमिक परिभाषा का हवाला देते हुए मूल्यांकन के लिए नहीं लिया जाना चाहिए।

34. प्रबंधन और गारंटी शुल्क पर ब्याज पर निगम का रुख यह है कि सी. एस. ई. पी. डी. आई.-टी. आर. आई. एस. एच. ई. कंसोर्टियम ने प्रबंधन शुल्क के रूप में 123.9746 करोड़ रुपये का हवाला दिया है। उनकी मूल्य बोली में गारंटी शुल्क के रूप में 392.0163 करोड़ है। शुल्क की मात्रा को लेकर कोई विवाद नहीं है। मूल्यांकन के दौरान सलाहकार ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड की टर्म शीट के अनुसार उपरोक्त शुल्कों पर 7.7 प्रति वर्ष की दर से ब्याज निर्धारित किया है, क्योंकि उपरोक्त शुल्क अपीलार्थी द्वारा चुकाए जाने वाले ऋण का हिस्सा हैं। यह कि यह निविदा शर्तों के साथ-साथ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई टर्म शीट और (इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड द्वारा जारी) दिनांकित स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी यहाँ पूरी ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा जिसमें वित्तीय शुल्क शामिल होंगे।

35. निगम ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत टर्म शीट से प्रासंगिक निविदा शर्तों का हवाला दिया है जो नीचे दिए गए हैं:- "निविदा के तहत बोलीदाताओं को निर्देश के खंड 14 (डी) । में निर्माण और वित्तपोषण लागत के दौरान कुल ईपीसी लागत + 100% ब्याज का कम से कम 75 प्रतिशत शामिल करने के लिए" ऋण राशि "को परिभाषित किया गया है। निविदा प्रबंधन शुल्क और गारंटी शुल्क के तहत बोलीदाताओं को निर्देश के खंड 14 (डी) 6 के अनुसार वित्तीय शुल्क/वित्तीय लागत का हिस्सा है। औद्योगिक और वाणिज्यिक द्वारा प्रस्तुत टर्म शीट में "ब्याज दर" से संबंधित शब्द के तहत बैंक ऑफ चाइना यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि उधारकर्ता प्रति वर्ष एक निश्चित दर पर पूर्ण ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत टर्म शीट में

"प्रबंधन शुल्क" के रूप में परिभाषित शर्तों के तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि ऋण राशि पर 1.5 प्रतिशत का प्रबंधन शुल्क ऋणदाता को वित्तीय समापन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर देय होगा। वित्तीय समापन के लिए छह महीने का समय दिया जाता है और इसलिए 60 दिनों की बाहरी सीमा को देखते हुए प्रबंधन शुल्क के मामले में 8 महीने का समय दिया जाता है।

इसी तरह "पूर्व शर्त" से संबंधित शर्तों के तहत, शर्त (घ) टर्म शीट निर्दिष्ट करती है कि याचिकाकर्ताओं से ऋण राशि के 95 प्रतिशत पर 5 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क (टर्म शीट में बीमा पॉलिसी कहा जाता है) लिया जाएगा और यह 6 वें महीने के अंत से देय होगा।

टर्म शीट के अनुसार राशि क्रमशः 8 वें और 6 वें महीने के अंत में याचिकाकर्ताओं के खाते में डेबिट हो जाती है।

सभी वित्तीय लागत औद्योगिक और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड से लिए गए ऋण का हिस्सा हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड द्वारा जारी किए गए दिनांक 21.10.2013 के स्पष्टीकरण के अनुसार, जो प्रत्यर्थी नं. आई. सी. बी. जी. द्वारा ली जाने वाली सभी लागतें और शुल्क ऋण वित्तपोषण का हिस्सा बनेंगे।

36. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि सलाहकार ने निविदा शर्तों के संबंध में प्रस्तावों का विश्लेषण किया है, चाहे यह माना जाए कि वित्तीय सलाहकार द्वारा किया गया विश्लेषण और निर्धारण दोनों पक्षों से किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज की प्राप्ति से पहले किया गया है। बी. एच. ई. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी श्री रोहतगी और निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्रसाद ने कहा कि मूल्यांकन परिभाषाओं पर आधारित है और किसी भी प्रकार की आकस्मिकता के लिए कुछ नहीं

छोड़ते हुए मूल्यांकन पर विचार किया गया है। श्री सिबबल की सलाहकार प्रस्तुति द्वारा मूल्यांकन के समय इस बात पर विचार किया गया है कि मूल्यांकन उतना ही दोषपूर्ण है जितना कि सलाहकार ने कुछ शुल्क लगाए हैं जिसके परिणामस्वरूप कीमत बढ़ गई है। उन्होंने टर्म शीट का उल्लेख किया है और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड द्वारा जो रखा गया है।

इस मोड़ पर हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि एक जटिल राजकोषीय मूल्यांकन में न्यायालय को संयम के सिद्धांत को लागू करना होगा। कई पहलुओं, खंडों, आकस्मिकताओं आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन गणनाओं को विशेषज्ञों और उन लोगों पर छोड़ दिया जाता है जिनके पास इस क्षेत्र में ज्ञान और कौशल है, इसमें शामिल वित्तीय गणना, बोली लगाने वाले की क्षमता और दक्षता और परियोजना को पूरा करने की व्यवहार्यता की धारणा को वित्तीय विशेषज्ञों और सलाहकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। न्यायालय वास्तव में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम वित्तीय सलाहकार के मूल्यांकन पर अपील नहीं कर सकते। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह न तो प्रत्यक्ष रूप से गलत है और न ही हम इसे विकृत या बेतुका होने के लिए त्रुटिपूर्ण मान सकते हैं।

37. मामले से अलग होने से पहले हम कुछ जोड़ने के लिए विवश हैं। हम बहुत दर्द के साथ ऐसा करते हैं। प्रत्यर्थी ने वित्तीय बोली को अंतिम रूप देने से पहले अभ्यावेदन की श्रृंखला प्रस्तुत की और मालिक की खामोशी को देखते हुए यह रिट अदालत के दरवाजे पर खटखटाया जिसने अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि उस स्तर पर उच्च न्यायालय को सावधानी बरतनी चाहिए थी। यदि अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग इस तरह से करती हैं तो इससे भ्रम पैदा होने और सार्वजनिक हित को भी खतरे में डालने की संभावना है। एक पीड़ित पक्ष उचित स्तर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है,

न कि जब बोलियों पर विचार किया जा रहा हो। हम निर्दिष्ट नहीं करना चाहते हैं। यह सराहनीय है कि कुछ प्रकार की निविदाओं में मालिक निष्पक्षता दिखाने के लिए बोलीदाताओं को बातचीत के लिए बुलाता है। लेकिन वर्तमान मामला इस तरह का नहीं है। एक बार मूल्य बोली खोले जाने के बाद, एक बोलीदाता अपने दम पर अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता था और कुछ पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए न्यायालय से एक आदेश की मांग नहीं कर सकता था। हमने इस पहलू पर केवल संयम के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की भूमिका को उजागर करने के लिए जोर दिया है।

38. हमारे पूर्ववर्ती विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए हमारी यह सुविचारित राय है कि खंड पीठ ने परिसीमन के माध्यम से एक अपीलीय मंच या प्राधिकरण के दृष्टिकोण को अपनाया है और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को कुछ क्षेत्रों तक विस्तारित किया है जिन पर वह नहीं हो सकता था और इसलिए, खंड पीठ के निर्णय और आदेश ने निरंतरता में त्रुटि के मार्ग का अनुसरण किया। नतीजतन, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि विवादित आदेश का कोई समाधान नहीं है और हम ऐसा निर्देश देते हैं। अंततः अपीलों की अनुमति दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।